

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 09 ● भोपाल ● 1-15 अक्टूबर, 2016 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

दो दिवसीय सहकारिता मंथन का शुभारंभ

सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने का नया आंदोलन : मुख्यमंत्री



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने का नया आंदोलन चलायें। सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार की अनंत संभावनायें हैं। सहकारिता लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का आंदोलन है। सभी प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं का कम्प्यूटरीकृत करें। उचित मूल्य की सहकारी दुकानों को बहुउद्देशीय बनायें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मनरेगा की मजदूरी का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाये। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ समन्वय भवन में सहकारिता मंथन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। बदलते परिवेश में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विचार-विमर्श के लिये दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग और सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सबसे पहले सहकारिता विभाग में सहकारी लोकपाल की व्यवस्था की जायेगी।

आंतरिक सर्तकता के लिये इस तरह की व्यवस्था सभी विभागों में की जायेगी। मध्यप्रदेश आज विकास दर और कृषि विकास दर में अक्ल है। विकास का प्रकाश गरीब तक पहुँचे तब ही विकास की सार्थकता है। संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। राज्य सरकार के गरीबों

के कल्याण के लिये एक रूपये किलो गेहूँ, एक रूपये किलो चावल और एक रूपये किलो नमक देने की योजना का क्रियान्वयन, गेहूँ के उपार्जन, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। समय पर कृषि ऋण की वसूली

किसानों के हित में है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, वनोपज तथा संतरे जैसे फलों के विपणन के लिये बेहतर काम हुआ है। अब सहकारी क्षेत्र को विस्तार कर आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण और स्व-सहायता समूहों से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिये।

सहकारिता विभाग ने ई-फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू कर बेहतर काम किया है। इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जायेगा।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सहकारी मंथन का समापन

पैक्स को बहुउद्देशीय बनाया जायेगा : श्री सारंग



भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि क पैक्स की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाते हुए सहकारी संस्थाओं के उत्पाद के साथ पतंजलि के लोकप्रिय उत्पादों को बेचा जायेगा। प्रदेश की घाटे में चल रही बैंकों सहित सभी जिला केन्द्रीय

सहकारी बैंकों में अपेक्स बैंक के अधिकारियों को पालक अधिकारी बनाया जायेगा। इसके जरिये बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की योजनाएँ लागू की जायेंगी। श्री सारंग ने बताया कि मंथन की सिफारिशों के आधार पर सहकारी क्षेत्र में समग्रता के साथ किसान,

गरीब और रोजगार के लिये पूरी दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ काम किया जायेगा। इस मौके पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा उपस्थित थे।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब समय आ गया है, जब सहकारिता गाँव, गरीब, किसान के साथ पूरे प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि किसान गरीब और पैक्स सोसायटी को केन्द्र में रखकर सहकारिता से हर व्यक्ति को जोड़ने की योजना बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि पैक्स सोसायटी से अभी तक सिर्फ उचित मूल्य पर खाद्यान्न का विक्रय किया जाता था। अब वहाँ लघु-वनोपज, दुग्ध संघ के साथ ही पतंजलि के उत्पादों जैसे साबुन, तेल सहित अन्य वस्तुएँ विक्रय के लिये रखी जायेंगी, जो लोगों की डिमांड में शामिल हैं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

पृष्ठ 1 का शेष

सहकारिता के माध्यम से रोजगार



सहकारिता विभाग में नवाचार विंग

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता विभाग ने छह माह का कलेण्डर बनाया है जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। सहकारिता विभाग में संवाद के लिये मंथन का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश आज देश में सबसे अधिक तेज गति से विकास कर रहा है। इसके पीछे हर

वर्ग से संवाद कर उनके कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं की भूमिका है। सहकारिता विभाग में नवाचार विंग बनाई गयी है जो अगले दो साल का रोडमैप बनायेगी। मंथन में दो दिन तक 9 समूह में अलग-अलग विषयों पर समूह चर्चा होगी। जिसके आधार पर दृष्टि-पत्र तैयार किया जायेगा। प्रदेश का हर किसान प्राथमिक सहकारी संस्था का सदस्य बने यह सुनिश्चित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश देश में विकास का मॉडल

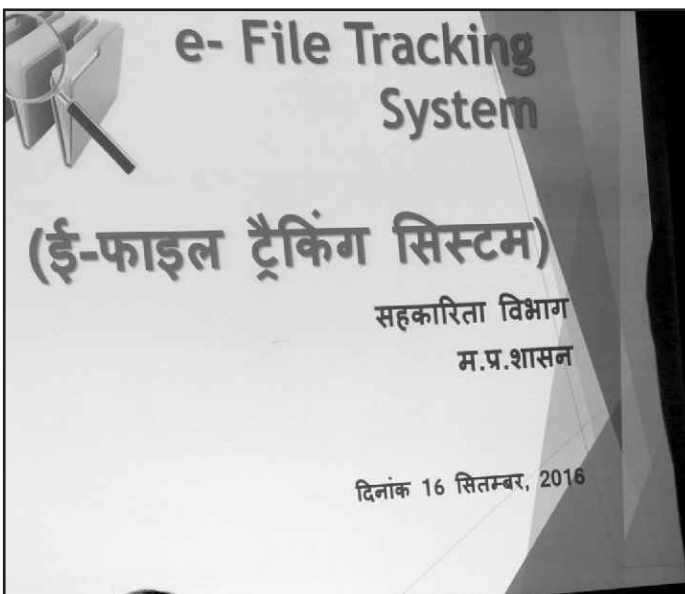
सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश आज देश में विकास के मॉडल के रूप में माना जाता है। गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की अहम भूमिका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का

वितरण सहकारिता के माध्यम से किया जाना चाहिये।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता विभाग की ई-फाइल ट्रेकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया तथा अपेक्स बैंक के ब्रांडिंग मैनुअल का विमोचन किया। उन्होंने सहकारिता विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। वसूली तथा लिंकिंग के लिये

श्रेष्ठ कार्य करने पर होशंगाबाद, रायसेन और बालाघाट की जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इसी तरह संभागीय शाखाओं में मुख्य शाखा भोपाल, अवधपुरी, एम.पी.नगर और पिपलानी शाखा के प्रबंधकों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में राज्य विपणन संघ के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, राज्य उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रतन यादव और राज्य वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने दिया तथा आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत अजीत केसरी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता विभाग तथा अपेक्स बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।



राज्य सहकारी संघ बनेगा कौशल उन्नयन की एजेंसी

संघ की आमसभा प्राधिकृत अधिकारी श्री अजीत केसरी की अध्यक्षता में सम्पन्न

भोपाल। राज्य सहकारी संघ के सशक्तिकरण के लिए इसे कौशल उन्नयन की नोडल एजेंसी बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि अन्य सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सके। उक्त उद्गार प्रमुख सचिव सहकारिता एवं प्राधिकृत अधिकारी राज्य सहकारी संघ श्री अजीत केसरी ने संघ मुख्यालय में संघ की आयोजित वार्षिक साधारण सभा में व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के लिये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है तथा प्रशिक्षण का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है एवं प्रशिक्षण का केन्द्रीयकरण किया गया है ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता के साथ वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र की अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को



व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने से उन्हे प्रशिक्षित मेन पावर मिलेगा। संघ द्वारा 58 हजार से अधिक को गत वर्ष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण सिंह तोमर ने राज्य/जिला संघों को सहकारी

क्षेत्र की विज्ञापन एजेंसी बनाने, संघ द्वारा संचालित एचडीसीएम के नियमित पाठ्यक्रम को पत्राचार से भी किये जाने, अभिदाय-अंशदान की पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र आगरा को उच्चजैन तथा नौगांव को ग्वालियर

स्थानांतरित करने की अपेक्षा की। सभा में श्री भगवती प्रसाद मिश्रा, श्री संतोष मीना तथा श्री सत्यनारायण झाला के अलावा अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिये। इस अवसर पर प्रतिनिधियों के अलावा अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप

नीखरा, आवास संघ के प्रबंध संचालक श्री आर.आर. सिंह तथा उपाभोक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रतन यादव उपस्थित थे। विषयों की प्रस्तुति एवं आभार श्री एस.एन. कोरी, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी संघ ने किया।

कृषि सहकारी साख समितियों में कृषकों की संख्या 69 लाख हुई

राज्य सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा



भोपाल। राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता को लेकर शासन ठोस कदम उठाने की ओर अग्रसर है। सहकारी साख समितियों में पात्र कृषकों की संख्या लगभग 69 लाख हो गई है। इनमें से 23 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर भी हैं। बैंक की अंशपूँजी 471 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ 81 लाख हो गई है। यह जानकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक श्री मनीष श्रीवास्तव ने बैंक के वार्षिक सम्मेलन में दी। इस

मौके पर बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा भी उपस्थित थे।

प्रशासक श्री मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार सुनियोजित नीति बना रही है। नीति के तहत पैक्स से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं के मौजूदा स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में इस दिशा में कार्य-

योजना बनाने के लिये दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम हुआ। मंथन में सहकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिसका समय-सीमा में क्रियान्वयन किया जायेगा।

प्रशासक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि शीर्ष बैंक स्तर पर किये गये योजनाबद्ध प्रयासों से बैंक के स्वयं के स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में बैंक

की अंशपूँजी 471.75 करोड़ थी, जो वर्ष 2015-16में बढ़कर 515.81 करोड़ हो गई। यह वृद्धि 9.34 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि बैंक की रक्षित निधि भी 589.47 करोड़ से बढ़कर 980.93 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि 66.41 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि बैंक के सीआरएआर में भी 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया गया है। प्राकृतिक आपदा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर खरीफ फसल के लिये दिये गये अल्पकालीन ऋण 5000 करोड़ को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जिससे 10 लाख 43 हजार किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि इसके लिये राज्य शासन ने बैंक को 3000 करोड़ की गारंटी दी। बैंक की स्थापना के बाद किसी एक वर्ष में ऋण परिवर्तन की यह सर्वाधिक राशि है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16में अल्पकालीन फसल

ऋण पर ब्याज अनुदान की 359 करोड़ 68 लाख की राशि जिला बैंकों को दी गई। यह भी किसी एक वर्ष में शासन से प्राप्त होने वाली सर्वाधिक राशि है।

प्रशासक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि बैंकों के प्रशासनिक सुधार की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये नई पदोन्नति नीति तैयार की गई है। सूचना तकनीक से जोड़ने के लिये इन्फर्मेशन पॉलिसी बनाई गई है और अपेक्स बैंक की पहचान बनाने के लिये ब्राँडिंग मेन्युअल लागू किया गया है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2015-16 में 2945 खरीदी केन्द्रों के जरिये 12 लाख किसानों से 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ, धान और मक्का की खरीदी की गई। बैठक में सदस्यों ने सहकारी साख आन्दोलन को मजबूत करने के लिये कई सुझाव दिये।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2016—भाद्र 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 14811-246-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक 6 सितम्बर 2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 सितम्बर 2016 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ.

- (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्,—

“परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का कोई आदेश या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा.”

धारा ६९-क का
स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सहकारी बैंक का
परिसमापन.

“६९-क. इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रिजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा १३-घ में वर्णित परिस्थितियों में या अन्यथा ऐसा अपेक्षित किया जाए, किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का तत्काल आदेश देगा.”

धारा ६९-ख का
संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६९-ख में,—

- पार्श्व शीर्ष में, शब्द “बीमाकृत बैंक” के स्थान पर, शब्द “बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक” स्थापित किए जाएं;
- उपबंध में दो बार आए शब्द “बीमाकृत बैंक” के स्थान पर, शब्द “बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक” स्थापित किए जाएं.

हर जिले में दिव्यांग बच्चों का विद्यालय स्थापित होगा

दिव्यांगों की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम सरकार भरेगी

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिये स्टेट रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जायेगा। साथ ही हर जिले में एक विद्यालय स्थापित किया जायेगा। दिव्यांग बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद की जायेगी। उनके लिये संचालित निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम राशि राज्य सरकार भरेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ शासकीय दृष्टि एवं श्रवण-बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस सेवा दिवस पर दिव्यांग बच्चों के बीच बोल रहे थे। श्री चौहान ने दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनमें क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वे थोड़े से प्रयास से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं।

भोपाल दुग्ध संघ ने किया प्रतिदिन 4.23 लाख लीटर दूध संकलन



भोपाल । भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2015-16के दौरान 2,389 दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से औसतन 4 लाख 23 हजार किलो लीटर प्रतिदिन दूध का संकलन किया गया। यह जानकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. के.के. सक्सेना ने भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की 34वीं वार्षिक साधारण सभा में दी। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष श्री धरमसिंह वर्मा ने की। सभा में 14 जिले के दुग्ध सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. सक्सेना ने बताया कि संघ द्वारा आलोच्य अवधि में शहरी उपभोक्ताओं को औसतन 3 लाख 55 हजार लीटर दूध प्रतिदिन पैकेट्स के रूप में और औसतन 19 हजार 662 लीटर प्रतिदिन मदर डेयरी दिल्ली को विक्रय किया गया। संघ ने 1218मीट्रिक टन घी भी विक्रय किया। सभा में बताया गया कि संघ के नवीन उत्पाद साँची मिल्क के लाइट लस्सी एवं पुदीना रायता का विक्रय भी प्रारंभ किया गया है।

संघ ने 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का नवीन पशु आहार संयंत्र सागर में इसी वर्ष आरंभ किया है। संघ ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 14 जिले में विकासखण्ड-स्तर पर प्राथमिक शालाओं एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों में शिशुओं के लिये 1424 मीट्रिक टन सुगंधित मीठा दुग्ध चूर्ण भी प्रदाय किया।

ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों के संरक्षण के लिये संघ श्रद्धा-निधि, सदस्य सहायता-निधि, लाइली बछिया, कृषक भ्रमण, पशुओं का डिवार्मिंग, वृक्षारोपण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनकी जानकारी भी वार्षिक साधारण सभा में दी गयी।

**पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)**

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल**

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039

फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160

Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in, cmctcbpl@rediffmail.com

(पृष्ठ 1 का शेष)

पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाया....

श्री सारंग ने कहा कि जिस तरह उचित मूल्य की दुकान है, उसी तरह उचित मूल्य पर बिल्डिंग मटेरियल की संस्थाएँ भी खोली जायेंगी। इससे एक ओर हमारे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वहीं आम उपभोक्ता को शुद्ध और सही कीमत पर निर्माण सामग्री मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र विशाल और अपार संभावनाएँ लिए हुए हैं। इस क्षेत्र में सही दिशा और दृष्टि के साथ काम करने की जरूरत है।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता में काम हो और निगरानी भी रहे, इसके लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारी लोकपाल में गठन की घोषणा कर पूरे देश में पहली बार एक अभिनव पहल की है। उन्होंने कहा कि पैक्स (ग्रामीण साख सहकारी समिति) का कम्प्यूटराइजेशन करने और इसे पूरी धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा से तय हो गया है कि सहकारिता क्षेत्र



की तस्वीर अब उज्ज्वल है और प्रदेश के विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है।

मंथन की अनुशांसा के क्रियान्वयन का केलेण्डर
राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि दो दिन चले सहकारी मंथन में 9

समूह में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, घाटे में चल रहे बैंकों को उबारने की रणनीति, उनके पालक अधिकारी की नियुक्ति जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि इन सभी बिन्दुओं

को समाहित कर अगले तीन दिन में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। इसके आधार पर कार्य-योजना बनाकर एक हफ्ते में इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जायेगा। कार्य-योजना पर होने वाले काम की प्रगति का मूल्यांकन तीन माह बाद किया जायेगा। इसकी

उपलब्धियों को लेकर अगले छह माह में एक बार फिर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंथन होगा।

दो-दिवसीय मंथन में 9 समूह द्वारा बैंकों को अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकों के समकक्ष रखने की कार्य-योजना, सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ एवं उन्नयन, सहकारी साख संरचनाओं में संभावित वित्तीय अनियमितताएँ, कारण एवं निवारण के उपाय, सहकारी बैंकों में नवीन कार्य-संस्कृति एवं मानव संसाधन विकास, पैक्स को बहु-उद्देश्यीय सेवा प्रदाता के रूप में विकसित करना, सहकारिता में नवाचार, सहकारी मूल्यों एवं सहकारी संस्थाओं के विकास में शीर्ष सहकारी संस्थाओं की भूमिका, सहकारिता के सुदृढीकरण के लिये कार्य-योजना और सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं रोजगार सृजन जैसे विषय पर विमर्श हुआ। इसके बाद सभी समूह ने अपने विषय से संबंधित बिन्दुओं को पॉवर प्वाइंट के जरिये प्रस्तुत किया। इस पर सभी समूह के बीच विमर्श हुआ और इसे अंतिम रूप दिया गया।

प्रशिक्षणार्थी अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र व भविष्य निर्माण में करें : श्री कोरी

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में एच.डी.सी.एम. सत्र का समापन



जबलपुर। सहकारी प्रबंध में उच्चतर पात्रोपाधि पाठ्यक्रम की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब प्रशिक्षार्थी परिश्रम और प्रयास से सहकारी विषयों का अध्ययन करें और प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र और आर्थिक भविष्य के निर्माण में करें ये विचार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के प्रबंध संचालक श्री एस.एन. कोरी ने गत दिवस सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर

में एच.डी.सी.एम. सत्र क्रमांक 13 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये।

आयोजन की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री पी.एस. तिवारी ने कहा कि राज्य सहकारी संघ का एच.डी.सी.एम. कोर्स आज अपनी उपयोगिता के कारण सहकारी ही नहीं वरन् निजी क्षेत्र में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। सहायक आयुक्त सहकारिता

श्रीमती आरती पटेल ने कहा कि इस पात्रोपाधि पाठ्यक्रम के माध्यम से सहकारिता में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। इस अवसर पर इफको के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक श्री आर.एस. तिवारी एवं मुख्य प्रबंधक श्री खेमचन्द्र नायक ने भी विशेष अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किये। व्याख्याता श्री अरुण कुमार जोशी ने सहकारी काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को



आकर्षित एवं प्रभावित किया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र एवं पात्रोपाधि पाठ्यक्रम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्री शशिकांत चतुर्वेदी द्वारा किया गया।

आयोजन में अतिथियों का स्वागत प्रशिक्षार्थियों की ओर से ग्रुप लीडर श्री मनोज गर्ग, श्रीमती पूजा उपाध्याय, श्रीमती चन्दा सिंह, श्रीमती संगीता जैन, श्री मनीष पटेल, श्री शोलेन्द्र पटेल, श्री अनीस पाठक इत्यादि द्वारा किया गया।

कृषि संबंधी जानकारी के लिये हिन्दी में सॉफ्टवेयर शुरू किया जाये

मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह से मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अक्टूबर माह में किसान सम्मेलन के बारे में बताया तथा उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 4,400 करोड़ की राशि के 20 लाख से अधिक किसानों के बीमा के दावे निपटाये जा चुके हैं। इसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों के खाते में जमा करवायी जा चुकी है। शेष 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाना है। श्री चौहान ने बताया कि किसान सम्मेलन में किसानों को प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मौके पर किसानों को प्रमाण-पत्र बाँटकर उनका



उत्वाहवर्धन करें।

श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आकलन के लिये जिले की बजाय क्षेत्र विशेष को आधार मानकर फसल के नुकसान का आकलन करने का आग्रह किया।

साथ ही यूनिकाइड पेकेज इश्योरेंस स्कीम में फसल बीमा करवाने वाले किसानों के लिये अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने योजना में स्थानीय आपदा जैसे- कीट-व्याधि को शामिल किये जाने

की माँग की। उन्होंने किसानों के लिये हिन्दी भाषा में ई-सॉफ्टवेयर बनाने की माँग की। अभी कृषि संबंधी जानकारी के लिये अंग्रेजी में ई-सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। साथ ही ई-प्लेटफार्म के मानक भी

निर्धारित किये जाना चाहिये। कृषि आधारित पोर्टल स्मार्ट-फोन पर खुलना चाहिये, ताकि किसान स्मार्ट-फोन पर जब चाहें और जहाँ चाहें कृषि पोर्टल खोलकर जानकारी ले सकें। श्री चौहान ने स्वाईल हेल्थ प्रबंधन के लिये मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये केन्द्र से 56 करोड़ शीघ्र जारी करने की माँग की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री को खाद के दाम कम करने पर धन्यवाद दिया। केन्द्रीय मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ने देश की कृषि को नई दिशा दी है। कृषि क्षेत्र में नये कीर्तिमान और नये प्रयोग किये गये हैं। अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिये।

राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाई



भोपाल। सहकारिता, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज अपने निवास से स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ल्ड विजन इंडिया इसके जरिये भोपाल शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएगा।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्वच्छता

का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। साफ-सफाई अगर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए तो बीमारियाँ हमसे कोसों दूर रहेंगी। उन्होंने वर्ल्ड विजन के प्रयास की सराहना की।

वर्ल्ड विजन अगले 10 दिन में भोपाल के विभिन्न स्थानों में जाकर साफ पीने के पानी का इस्तेमाल, शौच के लिए शौचालय के इस्तेमाल,

खुले में शौच के नुकसान, स्वयं की स्वच्छता, कब-कब और कैसे हाथ धोना है एवं किस तरीके से हाथ धोना है, के बारे में जागरूकता अभियान चलायेगी।

इस रथ के साथ नुक्कड़ नाटक की टीम, मेजिक शो, प्रश्न-उत्तरी एवं पुरस्कार वितरण के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जायेगा।

वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक

भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष भी एक से 7 अक्टूबर तक वन्य-प्राणी सप्ताह का आयोजन होगा। सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाएँ और शिविर होंगे।

सप्ताह का शुभारंभ एक अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे चित्रकला प्रतियोगिता से होगा। इसमें पहली से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थी तितलियाँ मेरे सपनों में, पाँचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थी मेरे मोहल्ले में एक पेड़, जो मोहल्ला है वन्य-जंतुओं का, नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थी भारतीय इतिहास, संस्कृति, मिथक में वन्य-प्राणी, खुला वर्ग प्रतियोगिता वन्य-प्राणी की हत्या हमारे भविष्य की हत्या है और निशक्तजन अपनी पसंद से चित्रकृति बनायेंगे।

सप्ताह के दौरान 2, 3, 4 और 6 अक्टूबर को सुबह 6.30 से 8.30 बजे तक वन विहार में पक्षी अवलोकन शिविर होगा। दो अक्टूबर को सर्प प्रदर्शनी एवं व्याख्यान और पर्यावरण स्वच्छता में गिद्धों की भूमिका पर कार्यशाला होगी। तीन अक्टूबर को फोटोग्राफी, शिक्षक वाद-विवाद प्रतियोगिता, वन्य-प्राणी संरक्षण में शिक्षकों की भूमिका पर शिक्षक कार्यशाला होगी। चार अक्टूबर को रंगोली प्रतियोगिता और संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ता पर्यटन वन्य-प्राणी संरक्षण के लिये घातक है पर विद्यालयीन वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी।

छह अक्टूबर को स्कूली बच्चों के लिये सृजनात्मक कार्यशाला एवं प्रतियोगिता के साथ कक्षा नवमी से बारहवीं के बच्चों के लिये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। सात अक्टूबर को फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता, खुला प्रश्न-मंच, फोटोग्राफी एवं पेंटिंग प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण के साथ सप्ताह का समापन होगा।

कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन करें

युवा किसान उद्यमी कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री चौहान



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन करें। हर जिले में युवा किसानों में से खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में युवा

उद्यमी तैयार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ भारतीय किसान संघ की युवा किसान उद्यमी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि

कार्यशाला, किसान संघ की रचनात्मक पहल है। मध्यप्रदेश में पिछले चार साल से कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ा है। अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिये रोड

मेप बनाया गया है। कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जा सकते हैं। कृषि के साथ जैविक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन-मत्स्य, पालन की गतिविधियों को जोड़ना होगा। कृषि उत्पादों के बहुआयामी उपयोग हो सकते हैं। कृषि उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था की जायेगी ताकि किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य मिल सके। जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था को सरल बनाया।

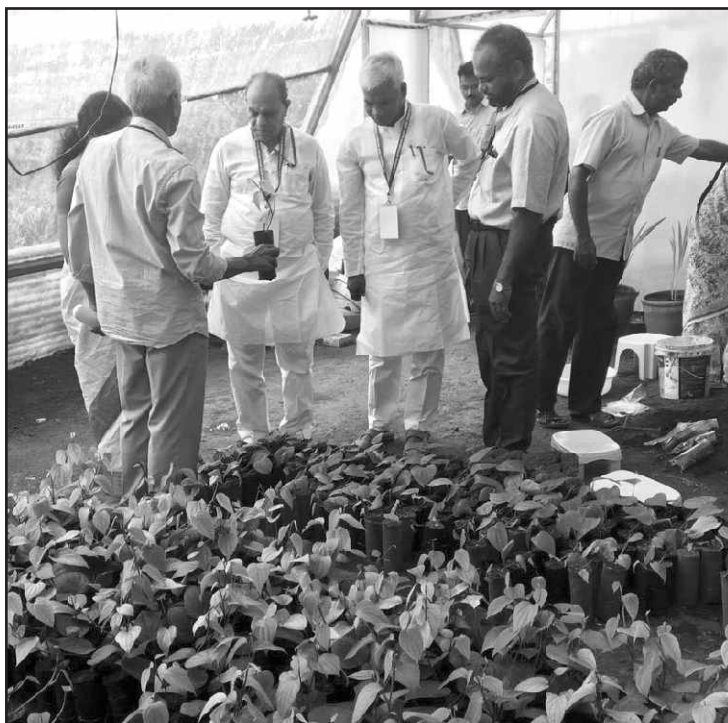
कार्यशाला में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि रोजगारयुक्त गाँव से ही स्वस्थ जीवन की नींव रखी जा सकती है। गाँवों में

रोजगार सृजन करने के लिये किसानों को प्र-संस्करण उद्योग में संरक्षण देना होगा। स्वावलंबी गाँव सम्पन्न हो सकते हैं।

क्षेत्रीय महामंत्री श्री शिवकांत दीक्षित ने कार्यशाला के विषय की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होना चाहिये। जैविक खेती को किसानों के अनुरूप बनाना चाहिये। जैविक उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था जरूरी है। कार्यशाला में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर केलकर, प्रदेश महामंत्री श्री राजेन्द्र पालीवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह और प्रदेश भर से आये युवा किसान उपस्थित थे।

कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कोझीकोड में मसाला खेती का अवलोकन किया

भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने केरल के कोझीकोड मसाला अनुसंधान केन्द्र में जाकर मसाला खेती का अवलोकन किया। कृषि मंत्री श्री बिसेन कोझीकोड के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र भी गये। उन्होंने मसाला खेती करने के तरीकों और उसके विपणन की प्रक्रिया जानी। श्री बिसेन ने कहा कि मध्यप्रदेश में मसाला खेती की काफी संभावनाएँ हैं। इससे हम खेती-किसानी से जुड़े हजारों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवा सकते हैं।



63वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह

मुख्य विषय : सहकारिता के माध्यम से सतत विकास एवं समृद्धि

- | | |
|------------|--|
| 14.11.2016 | शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जरिये से सहकारिता का सशक्तीकरण |
| 15.11.2016 | सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास |
| 16.11.2016 | सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन |
| 17.11.2016 | सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन |
| 18.11.2016 | सहकारिता में तकनीकी को अपनाना |
| 19.11.2016 | सहकारिता के माध्यम से युवाओं कमजोर वर्ग की महिलाओं का सशक्तीकरण |
| 20.11.2016 | सहकारिता के माध्यम से सुशासन, मूल्यों एवं नेतृत्व का विकास |

हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव मैनेजमेंट में

प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में दिनांक 03 अक्टूबर 2016 से बीस सप्ताह की अवधि के सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) में प्रवेश हेतु स्वाध्यायी/संस्थागत/विभागीय प्रशिक्षणार्थियों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क रुपये 6000/- है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी)। अभ्यर्थी 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी। पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर से संबंधित विषय भी सम्मिलित है।

आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क करें-

1. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान इन्दौर दूरभाष 0731-2410908 मो. 9826031440
2. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हनुमानताल जबलपुर दूरभाष 0761-2341338 मो. 9407059752
3. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र ई-8/77, शाहपुरा त्रिलंगा, भोपाल 0755-2725518 मो. 9425377233
4. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर दूरभाष 07685-256344 मो. 9826876158



**मध्यप्रदेश को कृषि में
सिरमौर बनाने वाले
किसान भाइयों के हित में
एक और बड़ा कदम...**

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

उर्वरक की दरों में कमी

खरीफ सीजन 2016 में माह जुलाई उपरांत फार्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की एम.आर.पी. में हुई कमी

उर्वरक का नाम	कृषकों की विक्रय दर प्रति बोरी खरीफ 2016		दरों में कमी प्रति बोरी (रु.)
	पूर्व में निर्धारित विक्रय दर (रु.)	नवीन विक्रय दर (रु.)	
डीएपी	1256.00	1150.38	(-) 105.62
एनपीके 12.32.16	1150.00	1097.00	(-) 53.00
जिकेटेड एनपीके 12.32.16	1171.50	1118.50	(-) 53.00
एनपीके 10.26.26	1145.00	1092.00	(-) 53.00
एनपीके 20.20.0.13	915.27	874.50	(-) 40.77
एमओपी	826.93	583.01	(-) 243.92



किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2016

मध्यप्रदेश जनसन्चर्क द्वारा जारी D-79680/2016